



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

No. 265]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2004/कार्तिक 18, 1926
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2004/KARTIKA 18, 1926

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2004

विषय : 1 जनवरी, 2005 से परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों की शेष व्यवस्थाओं का प्रचालन ।

संख्या 1/61/2004-निर्यात-1

(1) प्रस्तावना

- (1) जबकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार भारत से संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों और कनाडा को की जाने वाली कुछ वस्त्र उत्पाद श्रेणियों के निर्यात विनिश्चित वार्षिक मात्रा संबंधी प्रतिबंधों (वस्त्र कोटा सीमाओं) के भीतर प्रतिबंधित हैं ।
- (2) जबकि सरकार निर्यात आयात नीति के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के माध्यम से ऐसी वस्त्र उत्पाद श्रेणियों के निर्यात विनियमित कर रही है ।
- (3) जबकि वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार वस्त्र कोटा व्यवस्था पूर्णतया समाप्त कर दी जाएगी जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी, 2005 से "वस्त्र और क्लोदिंग" का सामान्य गॉट 1994 के नियमों में पूर्णतया एकीकरण हो जाएगा ।
- (4) जबकि, 31 दिसंबर, 2004 को कोटा व्यवस्था की समाप्ति पर परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/128/99-निर्यात-1 (इसके संशोधनों सहित) और इसके पूर्व की अधिसूचनाएं सह-अवधि आधार पर हैं ।
- (5) जबकि, परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के कुछ उपबंधों का प्रचालन कुछ अवधि के लिए अर्थात् प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए जारी रखने की आवश्यकता है । ऐसे उपबंधों का निरंतर प्रचालन जन हित और राष्ट्र हित में है तथा यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है :-

(क) ईएमडी के जल्ती संबंधी आदेशों से संबंधित अपील और पुनरीक्षा के उपबंधों को जारी रखना ।

(ख) कोटा दायित्वों को पूरा न किए जाने/कम पूरा किए जाने के मामलों को निपटाने के मौजूदा तंत्र को जारी रखना ।

(2) अधिसूचना

(6) इसलिए अब सरकार एतद्द्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अधिसूचना बनाती है ।

(1) दिनांक 31 दिसंबर, 2004 को परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/128/99-निर्यात-1 (इसके संशोधनों सहित) और इसके पूर्व की अधिसूचनाओं की समाप्ति से इन अधिसूचनाओं के शेष प्रकार्यों और विशेषकर निम्नलिखित उपबंधों का प्रचालन प्रभावित नहीं होगा :-

(क) कोटा नीतियों के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित कोटा संचालन प्रधिकारियों (क्यूएए) से संबंधित उपबंध ।

(ख) निर्यातकों द्वारा कोटा के दुरुपयोग से निपटने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध ।

(ग) वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षकीय भूमिका से संबंधित उपबंध ।

(घ) ईएमडी/बीजी/पीडीसी जब्त होने के खिलाफ की जाने वाली अपील से संबंधित उपबंध ।

(ङ) प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी), बैंक गारंटी (बीजी) और पूर्व दिनांकित चैक (पीडीसी) जब्त होने से संबंधित उपबंध ।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि उपर्युक्त अधिसूचना लागू रहती तो उस स्थिति में की जाने वाली कोई कार्रवाई अथवा उपाय शुरू किए जाते, जारी रहते अथवा लागू रहते और दिया गया अथवा लगाया जाने वाला कोई अन्य दण्ड, जल्ती अथवा सजा दी जाती ।

(3) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, वर्ष 1992 की संख्या 22 के उपबंध, मौजूदा अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए निरंतर लागू रहेंगे ।

सुधीर भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2004

Sub: **Operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2005.**

No. 1/61/2004-Exports-I*(I) Preamble:*

(i) Whereas, as per the WTO Agreement on Textiles & Clothing (ATC), exports of certain textile product categories from India to the United States, Member countries of European Union and Canada are circumscribed within the specified annual quantitative restraints (Textile Quota limits).

(ii) Whereas, the Government has been regulating the exports of such textile product categories by means of Export Entitlements (Quota) Policies notified under the provisions of Export Import Policy.

(iii) Whereas, as per ATC, the textile quota regime shall be completely abolished leading to full integration of "textiles and clothing" into normal GATT 1994 rules with effect from 1st January 2005.

(iv) Whereas, the Notification No.1/128/99-Exports-I dated 12th November 1999 (including its amendments) and the predecessor Notifications concerning Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy are co-terminus with the end of quota regime on 31st December 2004.

(v) Whereas, there is a need for continued operation of certain provisions of the Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies for a short duration, initially for a one year period, starting from 1st January 2005. Continued operation of such provisions is in public interest and in national interest, and is necessary for meeting the following objectives:-

- (a) to continue the appeal and review provisions in respect of EMD forfeiture orders.
- (b) to continue with the existing mechanism to deal with cases of non/short performance of the quota obligations.

(II) *Notification*

(vi) Now therefore, the Government hereby makes the following Notification, initially for a period of one year starting from 1st January 2005.

(1) The cessation of Notification No.1/128/99-Exports-I dated 12th November 1999 (including its amendments) and the predecessor Notifications concerning Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy on 31st December 2004 shall not affect the operation of the residuary functions of these Notifications, and in particular, of the following provisions contained therein:-

- a) Provisions relating to the Quota Administering Authorities (QAA) notified for implementation of various provisions of the Quota policies.
- b) Provisions relating to the procedure to deal with quota malpractices by exporters.
- c) Provisions relating to the supervisory role of the Textile Commissioner.
- d) Provisions relating to appeal against forfeiture of EMD/BG/PDC.
- e) Provisions regarding forfeiture of Earnest Money Deposit (EMD), Bank Guarantee (BG) and Post Dated Cheques (PDC).

(2) Apart from the above, any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, confiscation or punishment imposed or may be imposed or made as if the above Notifications had been in force.

(3) The provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 No. 22 of 1992 would continue to be applicable for the purposes of present notification.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2004

विषय : 1 जनवरी, 2005 से यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों की शेष व्यवस्थाओं का प्रचालन ।

संख्या 1/61/2004-निर्यात-1**(1) प्रस्तावना**

- (1) जबकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार भारत से संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों और कनाडा को की जाने वाली कुछ वस्त्र उत्पाद श्रेणियों के निर्यात विनिश्चित वार्षिक मात्रा संबंधी प्रतिबंधों (वस्त्र कोटा सीमाओं) के भीतर प्रतिबंधित हैं ।
- (2) जबकि सरकार निर्यात आयात नीति के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के माध्यम से ऐसी वस्त्र उत्पाद श्रेणियों के निर्यात विनियमित कर रही है ।
- (3) जबकि वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार वस्त्र कोटा व्यवस्था पूर्णतया समाप्त कर दी जाएगी जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी, 2005 से "वस्त्र और क्लोदिंग" का सामान्य गॉट 1994 के नियमों में पूर्णतया एकीकरण हो जाएगा ।
- (4) जबकि, 31 दिसंबर, 2004 को कोटा व्यवस्था की समाप्ति पर यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/129/99-निर्यात-1 (इसके संशोधनों सहित) और इसके पूर्व की अधिसूचनाएं सह-अवधि आधार पर हैं ।
- (5) जबकि, यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के कुछ उपबंधों का प्रचालन कुछ अवधि के लिए अर्थात् प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए जारी रखने की आवश्यकता है । ऐसे उपबंधों का निरंतर प्रचालन जन हित और राष्ट्र हित में है तथा यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है :-

(क) ईएमडी के जल्दी संबंधी आदेशों से संबंधित अपील और पुनरीक्षा के उपबंधों को जारी रखना ।

(ख) कोटा दायित्वों को पूरा न किए जाने/कम पूरा किए जाने के मामलों को निपटाने के मौजूदा तंत्र को जारी रखना ।

(2) अधिसूचना

- (6) इसलिए अब सरकार एतद्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अधिसूचना बनाती है ।
- (1) दिनांक 31 दिसंबर, 2004 को यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) - नीति से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/129/99-निर्यात-1 (इसके संशोधनों सहित) और इसके पूर्व की अधिसूचनाओं की समाप्ति से इन अधिसूचनाओं के शेष प्रकारों और विशेषकर निम्नलिखित उपबंधों का प्रचालन प्रभावित नहीं होगा :-

- (क) कोटा नीतियों के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित कोटा संचालन अधिकारियों (क्यूएए) से संबंधित उपबंध ।
- (ख) निर्यातकों द्वारा कोटा के दुरुपयोग से निपटने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध ।
- (ग) वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षकीय भूमिका से संबंधित उपबंध ।
- (घ) ईएमडी/बीजी/पीडीसी जब्त होने के खिलाफ की जाने वाली अपील से संबंधित उपबंध ।
- (ङ) प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी), बैंक गारंटी (बीजी) और पूर्व दिनांकित चैक (पीडीसी) जब्त होने से संबंधित उपबंध ।
- (2) उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि उपर्युक्त अधिसूचना लागू रहती तो उस स्थिति में की जाने वाली कोई कार्रवाई अथवा उपाय शुरू किए जाते, जारी रहते अथवा लागू रहते और दिया गया अथवा लगाया जाने वाला कोई अन्य दण्ड, जब्ती अथवा सजा दी जाती ।
- (3) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, वर्ष 1992 की संख्या 22 के उपबंध, मौजूदा अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए निरंतर लागू रहेंगे ।

सुधीर भार्गव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2004

Sub: **Operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2005.**

No. 1/61/2004-Exports-I

(I) *Preamble:*

(i) Whereas, as per the WTO Agreement on Textiles & Clothing (ATC), exports of certain textile product categories from India to the United States, Member countries of European Union and Canada are circumscribed within the specified annual quantitative restraints (Textile Quota limits).

(ii) Whereas, the Government has been regulating the exports of such textile product categories by means of Export Entitlements (Quota) Policies notified under the provisions of Export Import Policy.

(iii) Whereas, as per ATC, the textile quota regime shall be completely abolished leading to full integration of “textiles and clothing” into normal GATT 1994 rules with effect from 1st January 2005.

(iv) Whereas, the Notification No.1/129/99-Exports-I dated 12th November 1999 (including its amendments) and the predecessor Notifications concerning Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy are co-terminus with the end of quota regime on 31st December 2004.

(v) Whereas, there is a need for continued operation of certain provisions of the Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies for a short duration, initially for a one year period, starting from 1st January 2005. Continued operation of such provisions is in public interest and in national interest, and is necessary for meeting the following objectives:-

- (a) to continue the appeal and review provisions in respect of EMD forfeiture orders.
- (b) to continue with the existing mechanism to deal with cases of non/short performance of the quota obligations.

(II) Notification

(vi) Now therefore, the Government hereby makes the following Notification, initially for a period of one year starting from 1st January 2005.

(1) The cessation of Notification No.1/129/99-Exports-I dated 12th November 1999 (including its amendments) and the predecessor Notifications concerning Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy on 31st December 2004 shall not affect the operation of the residuary functions of these Notifications, and in particular, of the following provisions contained therein:-

- a) Provisions relating to the Quota Administering Authorities (QAA) notified for implementation of various provisions of the Quota policies.

- b) Provisions relating to the procedure to deal with quota malpractices by exporters.
- c) Provisions relating to the supervisory role of the Textile Commissioner.
- d) Provisions relating to appeal against forfeiture of EMD/BG/PDC.
- e) Provisions regarding forfeiture of Earnest Money Deposit (EMD), Bank Guarantee (BG) and Post Dated Cheques (PDC).

(2) Apart from the above, any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, confiscation or punishment imposed or may be imposed or made as if the above Notifications had been in force.

(3) The provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 No. 22 of 1992 would continue to be applicable for the purposes of present notification.

SUDHIR BHARGAVA. Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2004

विषय : जिन देशों के निर्यात, वस्त्र एवं क्लोदिंग करार के प्रावधान के अंतर्गत अवरोधों द्वारा कवर होते हैं, उनके संबंध में परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004)।

सं.1/61/2004-निर्यात-1 : उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 1/128/99 निर्यात-1 जिसे बाद में दिनांक 10 दिसंबर, 1999, 7 फरवरी, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना, 13 जून, 2000 की अधिसूचना सं.1/68/2000, 21 जुलाई 2000 की अधिसूचना सं. 1/21/2000-निर्यात-1, 20 नवंबर, 2000 की अधिसूचना सं. 1/133/2000-निर्यात-1, 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 13/33/2000-निर्यात-1, 24 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 1/149/99-निर्यात-1, 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. 1/21/2001, 30 अप्रैल 2001 की अधिसूचना सं. 1/161/2000-निर्यात-1, 6 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 1/15/2001-निर्यात-1, 28 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 1/73/2000-निर्यात-1, 9 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 1/59/2002-निर्यात-1, 20 नवंबर, 2002 की अधिसूचना सं. 1/23/2002-निर्यात-1 तथा 6 मई, 2003 की अधिसूचना सं. 1/52/2002-निर्यात-1, द्वारा संशोधित किया गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस अधिसूचना में निम्नलिखितानुसार आगे संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

2. पैरा 16 के उप-पैरा (ii), (iii) को हटा दिया जाएगा ।
3. तदनुसार, उसके बाद के उप-पैराओं को (ii) से (xii) तक दुबारा संख्या दी जाएगी ।
4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी ।

सुधीर भार्गव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2004

Sub: Garment and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provision of the Agreement on Textiles and Clothing.

No. 1/61/2004-Exports-I – 1. Attention is invited to Notification No.1/128/99 Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notifications of even number dated 10th December, 1999, 7th February, 2000, Notification No.1/68/2000 dated 13th June, 2000, Notification No.1/21/2000-Exports-I dated 21st July, 2000, Notification No.1/133/2000-Exports-I dated 20th November, 2000, Notification No.13/33/2000-Exports-I dated 8th January, 2001, Notification No.1/149/99-Exports-I dated 24th January, 2001, Notification No.1/21/2001 dated 30th April, 2001, Notification No.1/161/2000-Exports-I dated 30th April, 2001, Notification No.1/15/2001-Exports-I dated 6th March, 2002, Notification No. 1/73/2000/Export-I dated 28th May, 2002, Notification No. 1/59/2002-Export-I dated 9th July, 2002, Notification No. 1/23/2002-Exports-I dated 20th November, 2002 and Notification No. 1/52/2002-Exports-I dated 6th May, 2003 on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the notification as follows:-

2. The sub-paras (ii), (iii) of para 16 shall be deleted.
3. Accordingly, the subsequent sub-paras will be re-numbered as (ii) to (xii).
4. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

SUDHIR BHARGAVA, Jt. Secy.

33816204 = 150 + 10